भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2669
25 मार्च, 2022 को उत्तर देने के लिए

कृषि भूमि स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

2669. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि भूमि स्तर या ग्राम स्तर पर लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए जल्दी सड़ने वाले फलों और सब्जियों को चिह्नित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;और

(ग) वर्ष 2021-22 से आज की तारीख तक उक्त प्रयोजन के लिए आवंटित, संवितरित और उपयोग की गयी निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): जी हां, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के दीर्घकालिक उपायों के तहत सहायता के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 22 विकारी फसलों की पहचान की गई है।

फल (10): आम, केला, सेब, अनानस, संतरा, अंगूर, ओनला/आंवला, अनार, अमरूद, लीची

सब्जियां (11): टमाटर, प्याज, आलू, हरी मटर, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, लौकी परिवार [लौकी, करेला, तोरई, परवल और पेठा], भिंडी, लहसुन, अदरक।

समुद्री (1): झींगा

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन आंकड़ों के आधार पर प्रमुख उत्पादक राज्यों/जिलों में 22 फसलों के लिए क्लस्टरों की पहचान की गई है।

(ग): यह योजना मांग आधारित है और इस योजना के तहत कोई राज्य-वार/जिला-वार बजट आवंटित नहीं किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं पर दिनांक 21.03.2022 तक कुल 5.78 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। 5.78 करोड़ रुपये में से 4.32 करोड़ रुपये गुजरात राज्य में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के रूप में जारी किए गए हैं और महाराष्ट्र राज्य में संस्वीकृत परियोजना के लिए अनुदान सहायता के रूप में शेष 1.46 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****